मजिस्ट्रेट (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति) जहां कहीं निर्दिष्ट अथवा नियुक्त है, को समिति का सदस्य सचिव बनाया जाना चाहिए । समिति यह-देखने के लिए जिम्मेदार होगी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के मामलों की जोरदार ढंग से पैरवी हो तथा उन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जाए ।

(6) अनुसूचित जातियों/जनजातियों विरुद्ध अत्याचारों से संबंधित मामलों के शीघ्र जांच सुनिश्चित करने हेतु, विशेषकर संवेदनशील जिलों में, मंडल/जिला स्तर पर विशेष जांच प्रकोष्ठ बनाए जाएं।

(7) सरकार को न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी कर्मठता से करनी चाहिए तथा सतीय परीक्षणों की तरह इनके शीघ्र नपटान को सुनिश्चित करने हेतु दैनंदिन आधार पर इनकी सुनवाई के भरसक प्रयास किए जाएं ।

(8) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों पर अनेक अत्याचार भूमि विवादों के पैदा होते हैं । अतः भूमि के मामले के शीघ्र निपटान के तरीकों का अवश्य पता लगाया जाना चाहिए । इसी प्रकार विभिन्न न्यायालयों में लंबित भूमि विवादों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(9) अत्याचार के मामलों की जांच का उत्तरदायित्व सामान्य पुलिस तंत्र में निहित होना चाहिए उसका निकट पर्यवेक्षण जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निगरानी तथा मानीटरिंग समिति द्वारा किया जाना चाहिए ।

(10) समुचित मामलों में अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करने के लिए किसी लोकसेवक के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश का प्राधिकार उक्त समिति के पास होना चाहिए जैसाकि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में निर्धारित किया गया है । ऐसे मामलों में, खास तौर से मामले की जांच का कार्य जिला पुलिस से भिन्न किसी अन्य जांच एजेंसी जैसे सतर्कता ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, राज्य अपराध जांच विभाग आदि को सौंपा जाए ताकि यह विश्वास पैदा हो सके कि अपराधी को बचाया नहीं जाएगा ।

(11) ऐसे मामलों के अभियोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अभियोजकों का एक पृथक पैनल नियुक्त किया जाए ।

मध्य प्रदेश में "कुटीर ज्योति योजना" का कार्यान्वयन

*277. **श्री अजीत जोगी**
श्री बेकल "उत्साही" :

क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक जिलावार, कितने गांवों को विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है और कितने गांव ऐसे हैं जिनका अभी विद्युतीकरण नहीं हुआ है ;

(ख) इन जिलों में किन-किन स्थानों पर "कुटीर ज्योति योजना" को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ग) इन जिलों के कौन-कौन से गांवों में इस योजना को अभी कार्यान्वित किया जाना शेष है ; और

(घ) शत-प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री कनक मल राय**) : (क) से (घ) 30-10-1991 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण एवं अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है (नीचे देखिए) । उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 84%

गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष गांवों का विद्युतीकरण, निर्धारित लक्ष्यों और योजना आयोग द्वारा कुल उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत राज्य के लिए नियत निधियों पर निर्भर करेगा।

मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा "कुटीर ज्योति" योजना के अन्तर्गत राज्य में जारी किए गए सिंगल प्वाइंट लाइट कनैक्शनों की जिलेवार संख्या विवरण—II में दी गई है। 1988-89 तथा 1989 90 में केन्द्रीय अनुदान से वित्तपोषित इस स्कीम के अन्तर्गत, लाभभोगियों का पता लगाए जाने सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंपा गया था। इस स्कीम को 1 अप्रैल, 1991 से और आगे जारी नहीं रखा गया है।

विवरण-I

मध्य प्रदेश में 31 अक्तूबर, 1991 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत एवं अविद्युतीकृत गांवों की जिलेवार स्थिति

क्र० सं०	जिले का नाम	31-10-91 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	अविद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	भोपाल	544	—
2.	रायसेन	1226	199
3.	विदिशा	1256	263
4.	सीहोर	1009	3
5.	राजगढ़	1481	185
6.	होशंगाबाद	1224	199
7.	बेतूल	1178	148
8.	ग्वालियर	751	—
9.	दतिया	398	—
10.	मुरैना	1248	45
11.	भिण्ड	891	—
12.	गुना	1978	65
13.	शिवपुरी	1280	20
14.	इन्दौर	639	—
15.	खण्डवा	1063	28
16.	खारगोन	1651	185
17.	धार	1397	93
18.	झाबुआ	1163	160
19.	रतलाम	970	80
20.	मन्दसौर	1575	5
21.	उज्जैन	1098	1
22.	देवास	1032	36
23.	शाजापुर	1065	—
24.	जबलपुर	1053	321
25.	मण्डला	1805	297
26.	नरसिंहपुर	998	31
27.	सिवनी	1406	200
28.	बालाघाट	1122	155
29.	छिन्दवाड़ा	1094	19
30.	सागर	1632	236
31.	दमोह	991	202
32.	रीवा	1800	530
33.	सतना	1491	273
34.	छतरपुर	1074	—
35.	टीकमगढ़	880	—
36.	पन्ना	792	155
37.	सीधी	1686	135
38.	शहडोल	1625	343
39.	रायपुर	3293	560
40.	दुर्ग	1634	190
41.	राजनान्दगांव	1962	324
42.	बस्तर	2417	1069
43.	बिलासपुर	3032	496
44.	सरगुजा	1992	422
45.	रायगढ़	1837	358
	जोड़:	63433	8031

टिप्पणी : जिलेवार अविद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या (8031) और सारे

राज्य के सन्दर्भ में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या (71352–63433–7919) के बीच अन्तर) (112) इस तथ्य के कारण है कि 1971 की जनगणना के अनुसार कुछ गांवों जिन्हें पहले विद्युतीकृत किया जा चुका था, को अतिरिक्त (विद्युतीकृत) गांवों में शामिल कर लिया गया था और कुछ गांव, 1981 की जनगणना के अनुसार गैर-आबाद गांव थे।

विवरण II

मध्य प्रदेश में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों का जिलेवार ब्यौरा

क्र०सं०	जिला	कुल
1	2	3
1.	भोपाल	642
2.	रायसेन	2227
3.	विदिशा	1726
4.	सीहोर	1476
5.	राजगढ़	1548
6.	होशंगाबाद	2005
7.	बैतूल	3320
8.	ग्वालियर	1176
9.	दतिया	1594
10.	मुरैना	1600
11.	भिण्ड	1350
12.	गुना	1872
13.	शिवपुरी	1754
14.	इन्दौर	1004
15.	खण्डवा	2473
16.	खारगोन	6003
17.	धार	4422
18.	झाबुआ	5588
19.	उज्जैन	1561
20.	मन्दसौर	1243
21.	रतलाम	2202
22.	शाजापुर	1604
23.	देवास	1665
24.	जबलपुर	3232
25.	मण्डला	3830
26.	छिन्दवाड़ा	3034
27.	सिवनी	3387
28.	बालाघाट	2718
29.	नरसिंहपुर	1670
30.	सागर	2770
31.	दमोह	5197
32.	रीवा	2200
33	सतना	4243
34.	छतरपुर	1411
35.	टीकमगढ़	1538
36.	पन्ना	2700
37.	सीधी	3072
38.	शहडोल	7343
39.	रायपुर	7134
40.	दुर्ग	2721
41.	राजनन्दगांव	2301
42.	बस्तर	7874
43.	बिलासपुर	4809
44.	सरगुजा	4814
45.	रायगढ़	4190
	जोड़ :	132243

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि का आवंटन

*278. श्री रामदास अग्रवाल :
श्री ईश दत्त यादव

क्या वित्त मंत्री 26 नवम्बर 1991 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 62 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि